INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.828 (SJIF 2022)

डिजिटल इंडिया में सोशल मीडिया की भूमिका पर अध्ययन
(Study on Role of Social Media in Digital India)

Kanchan Jain	Dr. Yatendra Pal
Research Scholar Department of Education, Mangalayatan University, Aligarh (Uttar Pradesh, India)	Associate Professor Department of Education, Mangalayatan University, Aligarh (Uttar Pradesh, India)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/06.2022-62952359/IRJHIS2206017

सारांश :

डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, भारतमाला और सागरमाला जैसी भारत सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं का समर्थक और लाभार्थी हैं। 31 दिसंबर 2018 तक, भारत की आबादी 130 करोड़ (1.3 बिलियन), 123 करोड़ (1.23 बिलियन) आधार डिजिटल बायोमेट्रिक पहचान पत्र, 121 करोड़ (1.21 बिलियन) मोबाइल फोन, 44.6 करोड़ (446 मिलियन) स्मार्टफोन, 56 करोड़ थी। (560 मिलियन) इंटरनेट उपयोगकर्ता दिसंबर 2017 में 481 मिलियन लोगों (देश की कुल जनसंख्या का 35%) से अधिक हैं। एवं ई-कॉमर्स में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर या देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर सरकार की सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाये। ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना भी इसमें शामिल है। इसमें तीन मुख्य घटक शामिल हैं। सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी विकास, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना तथा सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता।

कीवर्ड : *नेटवर्क, उपलब्ध, ई-सर्विस, सेवाएं, केंद्र।*

प्रस्तावना :

नई डिजिटल सेवाऐ माध्यम से प्रदान की जाने वाली कुछ सुविधाएं भारत डिजिटल लॉकर, ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-साइन, ई-शॉपिंग और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल हैं। डिजिटल इंडिया के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने सफाई केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का उद्देश्य सभी फ्रंट-एंड सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन जनहित में लाना है। My Gov.in नीति और शासन के मामलों पर इनपुट और विचारों को साझा करने का एक सर्वोत्तम मंच है। यह चर्चा, करो और प्रसार दृष्टिकोण के माध्यम से शासन में नागरिक जुड़ाव के लिए एक मंच है।

उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस) भारत सरकार की एक ऑल-इन-वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी-चैनल मल्टी-प्लेटफॉर्म मल्टी-लिंगुअल मल्टी-सर्विस फ्रीवेयर मोबाइल ऐप है, जो 1,200 से

अधिक केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं को मल्टीपल में एक्सेस करने के लिए है। आधार, डिजिलॉकर , भारत बिल भुगतान प्रणाली,पैन ईपीएफओ सेवाएं, पीएमकेवीवाई सेवाएं, एआईसीटीई जैसी सेवाओं सहित एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज और यूएसएसडी (फीचर फोन) उपकरणों पर भारतीय भाषाओं शामिल किया गया है । सीबीएसई , कर और शुल्क या उपयोगिता बिल भुगतान, शिक्षा, नौकरी खोज, कर, व्यवसाय, स्वास्थ्य, कृषि, यात्रा, भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग, जन्म प्रमाण पत्र, ई-जिला, ई-पंचायत, पुलिस मंजूरी, पासपोर्ट, अन्य उपयोगिता सेवाएं निजी कंपनियां और कुछ अन्य ई-साइन फ्रेमवर्क नागरिकों को आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके ऑनलाइन दस्तावेज़ पर डिजिटल हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है।

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) मोबाइल ऐप का उपयोग लोगों और सरकारी संगठनों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। eHospital एप्लिकेशन महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है जैसे ऑनलाइन पंजीकरण, शुल्क का भुगतान और नियुक्ति, ऑनलाइन नैदानिक रिपोर्ट, ऑनलाइन रक्त की उपलब्धता की जांच करना इत्यादि।

सरकारी कर्मचारियों के वास्तविक समय के आधार पर उपस्थिति का रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोगी है। यह पहल दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में एक सामान्य बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) के कार्यान्वयन के साथ आरंभ हुई ।

बैक-एंड डिजिटलीकरण काला धन उन्मूलन: 2016 में, भारत के केंद्रीय बजट ने 11 प्रौद्योगिकी पहलों की घोषणा की एवं जिसमें कर चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए डाटा एनालिटिक्स का उपयोग शामिल है। जिससे आईटी कंपनियों के लिए आवश्यक सिस्टम बनाने का पर्याप्त अवसरों की उत्पत्ति हुई । डिजिटल साक्षरता मिशन छह करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लक्ष्य के साथ कार्य करेगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से देश में 550 किसान बाजारों को जोड़ने की योजना भी इसका उद्देश्य है। नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की सुविधाएं डिजिटल लॉकर सुविधा, नागरिकों को पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्टोर करने में सहयोग करेगी। डिजिटल लॉकर सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों तक सुरक्षित प्रदान करेगा। यह आधार द्वारा प्रदान की गई प्रामाणिकता सेवाओं का उपयोग करता है । इसका उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को समाप्त करके तथा सरकारी एजेंसियों में सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को साझा करने में सक्षम बनाता है। डिजिटल लॉकर के तीन प्रमुख हितधारक नागरिक, जारीकर्ता और अनुरोधकर्ता हैं।

बीपीओ एवं नौकरी में वृद्धि :

सरकार विभिन्न राज्यों में बीपीओ की 28,000 सीटें बनाने और राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है।

ई-संपर्क वर्नाक्युलर ईमेल सेवा 10% अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों में से केवल 2% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। बाकी

सभी अपना जीवन जीने के लिए अपनी स्थानीय भाषा पर ही निर्भर हैं।अभी तक, ईमेल पते केवल अंग्रेज़ी भाषा में ही बनाए जा सकते हैं। ग्रामीण भारत को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए, भारत सरकार ने जीमेल, ऑफिस और रेडिफ सहित ईमेल सेवा प्रदाताओं को क्षेत्रीय भाषाओं में ईमेल पता प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया है। ईमेल प्रदाता कंपनियों ने सकारात्मक संकेत दिखाए हैं, उसी प्रक्रिया में काम कर रही हैं। एक भारतीय-आधारित कंपनी, डाटा एक्सजेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ने 'डेटामेल' नाम से दुनिया का पहला मुफ्त भाषाई ईमेल पता लॉन्च किया है। जोकि 8 भारतीय भाषाओं, अंग्रेजी में ईमेल आईडी बनाने की अनुमति देता है; और तीन विदेशी भाषाएँ - अरबी, रूसी और चीनी एवं समय के साथ, डेटा एक्सजेन टेक्नोलॉजीज द्वारा 22 भाषाओं में ईमेल सेवा की पेशकश की जा सकेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिडनी डायलॉग को संबोधित करते हुए कहा - डिजिटल युग हमारे चारों ओर सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी और भारत की डिजिटल क्रांति के बारे में भी चर्चा की। अप्रैल 2017 तक भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या बढ़कर 500 मिलियन हो गई ।

28 दिसंबर 2015 को हरियाणा के पंचकुला जिले को डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत राज्य में सर्वश्रेष्ठ और शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला बनने के लिए सम्मानित किया गया।

भारत अब लगभग 10 मिलियन दैनिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को मासिक रूप से जोड़ रहा है एवं जो दुनिया में कहीं भी इंटरनेट समुदाय में जुड़ने की उच्चतम दर है।

डिजिटल इंडिया के उद्देश्य :

1:- **ब्रॉडबैंड हाइवे -** सड़क हाइवे की तरह ,ब्रॉडबैंड हाइवे से शहरों को जोड़ा जाएगा।

2:- सभी भारतीय नागरिकों की टेलीफ़ोन सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जा सकेगी।

3:- सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम जिसके जिसके अंतर्गत इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

4:- ई-गवर्नेंस - इस तकनीक के माध्यम से शासन- प्रशासन में नए सुधार लाये जा सकेगे।

5:- ई-क्रांति - विभिन्न सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा।

6:- इंफ़ोर्मेशन फ़ॉर ऑल अर्थात् सभी को जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

7:- इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन - भारत सरकार का लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कल-पुर्जों के आयात को शून्य करने से है।

8:- आईटी फ़ॉर जॉब्स यानी सूचना प्राद्योगिकी के माध्यम से अधिक नौकरियां बढ़ाई जा सकेगीं।

9:- अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम - जिसका संबंध विद्यालयों- महाविद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की हाज़िरी से है।

सोशल मीडिया की भूमिका :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के डिजिटल इंडिया अभियान को सोशल साइट्स पर भरपूर सहयोग मिल रहा है। **अमेरिका में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से मुलाकात** के पश्चात मोदी ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर को नए अंदाज में पोस्ट किया है।

डिजिटल इंडिया के समर्थन में उनका यह परिवर्तन लाखों लोगों को रास आया है। देखते ही देखते फेसबुक प्रोफाइल फोटो को मोदी अंदाज में पोस्ट करने की लोगों में जबरदस्त होड़ मच गई है। ट्विटर पर भी अभियान की चर्चा का बाजार लगातार सुर्खियों में है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तकनीक के माध्यम से आम लोगों का जीवन सरल बनाना है। डिजिटल इंडिया सप्ताह में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित मोबाइल ऐप भी जारी किए जाएंगे। ***अनुपम साराफ़ ने ट्वीट किया,*** 'क्या ज़बरदस्त शुरुआत है?

शंभू भारती ने लिखा है, 'अब बनेगा भारत महान।'

सुबोध प्रभु ने कहा, 'लेकिन बीएसएनएल ने तो मुझे लैंडलाइन और इंटरनेट देने से इनकार कर चुका है।'

संदर्भ :

1. प्रकाश, अमित। "डिजिटल इंडिया को लोकल जाने की जरूरत है"। द हिंदू । 26 फरवरी 2017 को लिया गया।
2. मन्नाथुकरेन, निसिम। "डिजिटल इंडिया का भव्य भ्रम" । द हिंदू । 26 फरवरी 2017 को लिया गया ।
3. सरकार जल्द ही आधार-ड्राइविंग लाइसेंस को लिंक करना अनिवार्य कर देगी: श्री रविशंकर प्रसाद , इंडियन एक्सप्रेस, 7 जनवरी 2019।
4. "इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया" । www.iamai.in । मूल से 27 जून 2018 को संग्रहीत किया गया । 3 मई 2018 को लिया गया ।
5. "यहां आपको डिजिटल इंडिया पहल के बारे में जानने की जरूरत है" , दैनिक समाचार और विश्लेषण , मुंबई , 28 सितंबर 2015
6. "रिमोट बंदाहल्ली गांव में सरकारी स्कूल मेक इन इंडिया से प्रेरित हो जाता है" , द न्यू इंडियन एक्सप्रेस , 15 मार्च 2016

7. "डिजिटल इंडिया वीक: डिजिटल लॉकर, MyGov.in, और अन्य परियोजनाओं का अनावरण किया गया" द इंडियन एक्सप्रेस, 5 जुलाई 2015
8. "जीएसटी कई ई-कॉमर्स फर्मों के कर मुद्दों की देखभाल करेगा: आईटी मंत्री", लाइव मिंट , 21 नवंबर 2014
9. "डिजिटल इंडिया फॉर आत्मानबीर भारत - ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल एरियाज़" । आत्मनिर्भार सेना । 20 नवंबर 2020।
10. "भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के बारे में", भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
11. सुब्रमण्यम, निखिल (22 मार्च 2013), "भारत का 'शानदार' ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए" ।
12. "सरकार बोटनेट सफाई केंद्र स्थापित करेगी", प्रीव्यू टेक , 25 मई 2014
13. जोन्स, क्लेयर (16 दिसंबर 2019)।
14. "भारत की भुगतान क्रांति"फाइनेंशियल टाइम्स । 16 दिसंबर 2019 को लिया गया ।
15. "मोदी की वेबसाइट को नया, मोबाइल के अनुकूल रूप मिलता है", बिजनेस स्टैंडर्ड , नई दिल्ली , बीएस रिपोर्टर, 16 जनवरी 2016
16. "सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए उमंग ऐप का अनावरण किया।", इकोनॉमिक टाइम्स, 23 नवंबर 2017।
17. "डिजिटल इंडिया हेल्थ समिट हेल्थटेक की भूमिका को मान्यता देता है" । ETHealthworld.com । 16 दिसंबर 2019 को लिया गया ।
18. "सभी सरकारी अस्पतालों में ई-अस्पताल प्रबंधन प्रणाली होगी" । बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया । प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 10 जून 2019 । 16 दिसंबर 2019 को लिया गया ।
19. "Atendance.gov.in: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की", द इकोनॉमिक टाइम्स, 7 अक्टूबर 2014
20. "Atendance.gov.in - सरकारी कार्यालय अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, सौजन्य नरेंद्र मोदी", दैनिक समाचार और विश्लेषण , 7 अक्टूबर 2014
21. मेंडोंका, जोशेल (29 फरवरी 2016), "बजट 2016: डिजिटल इंडिया ड्राइव को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी पहल" , द इकोनॉमिक टाइम्स
22. "सरकार का लक्ष्य किसानों को 'डिजिटल इंडिया' का लाभ देना है: पीएम मोदी", द टाइम्स ऑफ इंडिया , 18 फरवरी 2016
23. "क्या डिजिलॉकर डिजिटल इंडिया को उत्प्रेरित कर सकता है? - अधिकतम शासन" । मैक्सिममगवर्नेंस डॉट कॉम । 4 सितंबर 2016 । 8 सितंबर 2016 को लिया गया ।
24. "डिजिलॉकर - ऑनलाइन दस्तावेज़ भंडारण सुविधा भारत का राष्ट्रीय पोर्टल", india.gov.in , मूल से 15 मई 2015 को संग्रहीत
25. "डिजिटल इंडिया पहल के तहत: सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया", द इंडियन एक्सप्रेस , 28 फरवरी 2016